पर्यावरण और उपभोक्ता सुरक्षा फाउंडेशन

बनाम

भारत संघ और अन्य

(लिखित याचिका (सिविल) संख्या 659/2007)

11 अगस्त, 2017

[मदन बी. लोकुर और दीपाक गुप्ता, जेजे.]

महिला कल्याण/विकास-पुनर्वास के लिए लिखित याचिका वृंदावन में रहने वाली विधवाओं की संख्या-एक लेख के आधार पर जिसमें रहने वाली विधवाओं की दयनीय और चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है। वृंदावन-भारत संघ और उत्तर प्रदेश राज्य को विधवाओं के पुनर्वास के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका कि गरिमा के साथ रह सकें-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला और बाल विकास मंत्रालय और उत्तर प्रदेश राज्य जैसे संबंधित अधिकारियों द्वारा दायर विभिन्न रिपोर्टों में कहा गया हैः उच्चतम न्यायालय द्वारा समिति गठित करने का निर्देश दाखिल की गई सभी रिपोर्टों का अध्ययन करें और रिपोर्टों में दिए गए सुझावों के आधार पर एक सामान्य कार्य योजना प्रदान करें-समिति ने विधवा पुनर्विवाह के मुद्दे पर विचार करने का भी अनुरोध किया-भारत का संविधान अनुच्छेद 21 – जनहित याचिका (पीआईएल)-सामाजिक न्याय-सामाजिक रूप से वंचित समूह-वृंदावन में रहने वाली विधवाएँ। जनहित याचिका-चर्चा के लाभ।

निर्देश जारी करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 इसमें बहुत कम या कोई संदेह नहीं हो सकता है कि विधवाएँ देश के कुछ हिस्सों में सामाजिक रूप से वंचित हैं और कुछ हद तक बहिष्कृत किया गया। शायद यही कारण है कि उनमें से कई वृंदावन और अन्य आश्रमों में आने का विकल्प चुनते हैं, जहां दुर्भाग्य से, उनके साथ उस सम्मान के साथ व्यवहार नहीं किया जाता है जिसके वे हकदार हैं। यह बात स्पष्ट है। उस लेख से जो इस जनहित याचिका का कारण बना और उन रिपोर्टों के संकलन से जो इस मुकदमे ने उत्पन्न की हैं। यह है कि इन असहाय विधवाओं को आवाज दें कि इस न्यायालय के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्य के एक हिस्से के रूप में और सामाजिक न्याय के कारणों से उचित निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया है। [पैरा-18] [475-बी-सी]

1.2 रिपोर्टों में सभी संबंधितों द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ नहीं जाने चाहिए- इसका लाभप्रद रूप से उपयोग किया जाना चाहिए, एक अर्थ में व्यावहारिक और व्यवहार्य सुझावों की सोने की खान। तदनुसार, इसमें दाखिल सभी रिपोर्टों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। अदालत और दो महीने की अवधि के भीतर एक सामान्य कार्य योजना (रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के आधार पर) प्रदान करें। 30 नवंबर, 2017 को या उससे पहले का कोई भी मामला। [पैरा 11] [472-ई-एफ]

1.3 सुनवाई के दौरान जिन मुद्दों को संबोधित किया गया उनमें से एक विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया था। यह उम्मीद का विषय है कि हमारा समाज विधवाओं के प्रति पुराने ख्यालात को छोड़ दे। कमेटी से यह निवेदन किया जाता है कि वह अपनी रिपोर्ट में इस बात को ध्यान में रखे।

2.1 जनहित याचिका का लाभ न केवल समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है, बल्कि सामाजिक अक्षमताओं से पीड़ित लोगों को सशक्त बनाना जो शायद नहीं अनिवार्य रूप से उनके निर्माण का होना चाहिए। वृंदावन की विधवाएँ (और वास्तव में अन्य आश्रमों में) स्पष्ट रूप से हमारे समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्ग की इस श्रेणी में आते हैं। [पैरा 15] [474-ए-बी]

2.2 जनहित याचिका सम्मेलन का पहला चरण स्वयं मुख्य रूप से हाशिए पर पड़े समूहों के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण के साथ और समाज के ऐसे वर्ग जो अत्यधिक गरीबी, निरक्षरता के कारण और अज्ञानता इस न्यायालय या उच्च न्यायालयों से संपर्क नहीं कर सकती। इसमें जोड़ा गया है-सामाजिक रूप से वंचित समूह। ये हैं। जिन लोगों के पास न्याय तक कोई वास्तविक पहुंच नहीं है और उस अर्थ में वे आवाजहीन हैं, और ये वे लोग हैं जिन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है और जिनके उद्देश्य को उन लोगों द्वारा समर्थित करने की आवश्यकता है जो वंचितों के लिए सामाजिक न्याय की वकालत करते हैं। [पैरा 16] [474-सी-डी]

उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल (2010) 3 एससीसी 402: [2010] 1 एससीआर 678; लोक संघ के लोकतांत्रिक अधिकार बनाम। भारत संघ (1982) 3 एससीसी 235: [1983] 1 एस. सी. आर. 456 और दिल्ली जल बोर्ड बनाम राष्ट्रीय सीवरेज़ और संबद्ध क्षेत्रों की गरिमा और अधिकारों के लिए अभियान श्रमिक (2011) 8 एस. सी. सी. 568: [2011] 12 एस. सी. आर. 34-निर्भर पर।

मामला कानून संदर्भ

[1983] 1 एससीआर 456	उस पर भरोसा करें	पैरा 14
[2010] 1 एससीआर 678	उस पर भरोसा करें	पैरा 16
[2011] 12 एससीआर 34	उस पर भरोसा करें	पैरा 17

सिविल मूल क्षेत्राधिकारः लिखित याचिका (सिविल) सं 659/2007

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

2012 डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 168 और 133।

रंजीत कुमार, एस. जी., जुगल किशोर गिल्डा, डी. के. सिंह, ए.ए. जी. मेंदिरत्ता, निश्चल कुमार, सुश्री विमला सिन्हा, विभु शंकर मिश्रा, राज बहादुर यादव, आर. आर. राजेश, सुश्री सुषमा सूरी, जी. एस. मक्कर, एस. एन. तेरदल, डॉ. एस. के. वर्मा, सुश्री गार्गी तुली, अरिंदम मुखर्जी, सुश्री अपर्णा भट, सुश्री जोशिता पाई, गोपाल सिंह, श्रेयस जैन, अनिरुद्ध पी. मयी, सी. महिंद्रा, ए. सेल्विन राजा, ए. एम. ओझा, चिराग जैन, डी. एस. माहरा, वरिंदर कुमार शर्मा, अब्राहम सी. मैथ्यूज, निशे राजन शोंकर, श्रीमती अनु के. जॉय, वी.सुश्री नंदिनी सेन, चंचल गांगुली, के. वी. जगदीशवरन, श्रीमती जी. इंदिरा, वी. जी. प्रगसम, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यन, सुदर्शन सिंह रावत, अधिवक्ता उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय मदन बी. लोकुर, जे. द्वारा दिया गया था।

1. ये याचिकाएं दायर की गई थीं और जनहित में ली गई थीं, जिनका उद्देश्य वृंदावन और देश के अन्य आश्रमों में विधवाओं की जीवन में कुछ धूप वापस लाना है। यह अफ़सोस की बात है कि इन विधवाओं के साथ इतना दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया गया है, जैसे कि वे गरिमापूर्ण जीवन जीने के हकदार नहीं हैं और जैसे कि वे संविधान के अनुच्छेद 21 के संरक्षण के हकदार नहीं हैं।

2. याचिकाकर्ता, पर्यावरण और उपभोक्ता संरक्षण फाउंडेशन एक पंजीकृत धर्मार्थ संस्था और एक गैर-राजनीतिक निकाय है। यह. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अनिवार्य रूप से एक उपयुक्त रिट के लिए एक याचिका दायर की जिसमें भारत संघ

और उत्तर राज्य की आवश्यकता होती है। प्रदेश वृंदावन की विधवाओं के पुनर्वास के लिए सभी कदम उठाएगा ताकि उन्हें एक ऐसे स्तर पर लाया जा सके जहां वे सम्मान के साथ रह सकें।

3. यह याचिका अतुल सेठी द्वारा लिखे गए और नई दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया का 25 मार्च, 2007 का संस्करण में प्रकाशित एक लेख 'व्हाइट शैडो ऑफ वृंदावन' के आधार पर दायर की गई थी। लेख का उद्देश्य विधवाओं की दयनीय और चौंकाने वाली स्थितियों की रिपोर्ट करना और जनता और सरकारी एजेंसियों के ध्यान में लाना था। ऐसा करने का मौका, यह कहते हुए कि अब यह हमारा घर है।

4. लेखक के अनुसार, विधवाएँ कुछ आश्रमों या मंदिरों में इकट्ठा होती हैं जहाँ वे भजन गाती हैं और उन्हें लगभग 18 रु में प्रतिदिन लगभग 7 से 8 घंटे गाना होता था। उनका बाकी समय सड़कों पर भीख माँगने में बीतता है। उनमें से कई अपनी देखभाल करने के लिए बहुत बूढ़े हैं। दूसरों को उनकी देखभाल के लिए अपने संसाधनों को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, लेख वृंदावन में विधवाओं की जीवन स्थितियों की एक दुखद और निराशाजनक तस्वीर पेश करता है।

5. लेख को पढ़ने पर, याचिकाकर्ता ने मथुरा में जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र संबोधित किया और इसकी सामग्री को उनके संज्ञान में लाया और उसमें क्या कहा गया था, इस बारे में और जानकारी मांगी। याचिकाकर्ता को इस आशय का जवाब भेजा गया था कि विधवाओं की जीवन स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहाँ कुछ था इस संबंध में कुछ महीनों के लिए पत्राचार लेकिन कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह घटनाओं का क्रम है जिसने याचिकाकर्ता को उपरोक्त प्रार्थना के साथ इस न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए राजी किया।

6. इस न्यायालय ने जनहित में याचिका को लिया और कुछ महत्वपूर्ण दिशाएँ पारित कर दिया- उदाहरण के लिए, 14 नवंबर, 2008 को राष्ट्रीय महिला आयोग को एक तैयार करने का निर्देश दिया गया था विधवाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर व्यापक रिपोर्ट। यह भी था निर्देश दिया कि रिपोर्ट में विधवाओं के आयु वर्ग, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और इस मामले के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक अन्य सभी जानकारी होनी चाहिए।

7. 1 अप्रैल, 2011 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भारत सरकार में प्रत्यर्थियों में से एक के रूप में शामिल किया गया था और 9 मई, 2012 को इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि विधवाओं के दुख को कम करने के लिए, वृंदावन में निराश्रितों की पहचान और गणना का अभ्यास करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए-दोनों जिनके पास आश्रय है और जो घर में भटक रहे हैं और दूसरे जो बिना किसी आश्रय के सड़कों पर भटक रहे है। समिति को विधवाओं की पूरी जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता थी, जिसमें उनके वृंदावन में स्थानांतरित होने का कारण और उनके परिवार और उनके वर्तमान स्रोत के बारे में विवरण शामिल थे।

8. समय-समय पर कई अन्य आदेश पारित किए गए। विशेष रूप से 2015 के बाद से जब सामाजिक न्याय पीठ भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित। नतीजतन, एक बहुत बड़ी संख्या में रिपोर्ट तैयार की गई और संबंधित अधिकारी जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला और बाल विकास मंत्रालय और उत्तर प्रदेश राज्य ने वृंदावन की विधवाओं की समस्याओं में काफी रुचि लेनी शुरू कर दी। समय-समय पर तैयार की जाने वाली रिपोर्ट इस प्रकार हैः

1. जयप्रकाश सामाजिक परिवर्तन संस्थान डी. डी.-18/4/1, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700 064 द्वारा तैयार की गई पश्चिम बंगाल के धार्मिक स्थानों में

विधवाओं की स्थिति विश्लेषण की सारांश रिपोर्ट (अदिनांकित), जिसे 2012 के डब्ल्यू. पी. No.133 में दाखिल किया गया है।

2. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट (दिनांकित नहीं) महिला आयोग।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 2009-10 में वृंदावन में विधवाओं पर अध्ययन।

4. 10 मई, 2011 को महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव की आयोजित बैठक के कार्यवृत्त।

5. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2012 के डब्ल्यू. पी. सं. 133 में दिनांक 26 जुलाई, 2012 को दायर की गई रिपोर्ट दिनांकित 14 जुलाई, 2012

6. 10 सितंबर, 2012 की एक रिपोर्ट जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 03-08-2012 और सचिव जिला कानूनी सेवा द्वारा तत्काल आवश्यक कुछ सुधारों के साथ कुछ जमीनी वास्तविकताएँ प्राधिकरण, एडिशनल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा। यह है। 2012 के डब्ल्यू. पी. सं. 133 में दाखिल किया गया।

7. वृंदावन और राधाकुंड, मथुरा (यू. पी.) में रहने वाली वृद्ध और विधवाओं की दुर्दशा-एक सर्वेक्षण जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, मथुरा द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2012 की रिपोर्ट। यह 2012 के डब्ल्यू. पी. सं. 133 में दाखिल किया गया है।

8. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय कानूनी सेवाओं की रिपोर्ट प्राधिकरण दिनांक 14 जनवरी, 2014 को डब्ल्यू. पी. संख्या 133 में दायर किया गया 2012 12 सितंबर, 2014 को।

9. सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट मथुरा दिनांक 31 मार्च, 2014।

10. सुश्री रेणुका कुमार द्वारा 61 अप्रैल 2015 को स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई।

11. महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव द्वारा 2 सितंबर, 2015 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त।

12. राज्य की ओर से 11 मार्च, 2016 को दायर स्थिति रिपोर्ट उत्तर प्रदेश।

13. सुश्री रेणुका कुमार द्वारा 19 अप्रैल, 2016 को दी गई रिपोर्ट यू. पी. महिला कल्याण निगम द्वारा प्रशासित घर।

14. राष्ट्रीय महिला आयोग पर की दिनांक 28 अप्रैल, 2016 की स्टेटस रिपोर्ट द्वारा की गई सिफारिशें।

15. सुश्री रेणुका कुमार द्वारा 31 अगस्त, 2016 को प्रस्तुत बजट आवश्यकता के साथ स्टेटस रिपोर्ट।

16. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के स्वाधार गृहों में विधवाओं पर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नवंबर, 2016 की रिपोर्ट।

17. 8 नवंबर, 2016 को सुश्री रेणुका कुमार द्वारा वृंदावन में महिलाओं, विधवाओं और निराश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधाओं पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट।

18. महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिनांकित आदेश के संबंध में 2 जून, 2017 को दायर अनुपालन में शपथ पत्र 21अप्रैल, 2017।

9. उपलब्ध रिपोर्टों और सामग्री की अधिकता के साथ और सभी विद्वान वकीलों की गहरी भागीदारी के साथ, और वृंदावन की विधवाओं की असुविधा को कम करने के लिए हमें सहमत निर्देश जारी करने का अनुरोध करना अधिक उचित होगा। 29 मार्च, 2017 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

> "सुश्री अपर्णा भट, विद्वान वकील राष्ट्रीय महिला आयोग और श्री ए.के. पांडा, महिला मंत्रालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील और सुश्री पुष्पा बिष्ट द्वारा सहायता प्राप्त बाल विकास, महिला और बाल मंत्रालय में उप सचिव विकास का कहना है कि सहमति होने पर यह उचित होगा निर्देश तैयार किए जाते हैं और जारी किए जाते हैं ताकि तत्काल कदम उठाए जा सकें अलग-अलग क्षेत्रों में विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए लिया जाता है देश के कुछ हिस्सों में।
>
> पक्षों के विद्वान वकील का कहना है कि या तो वे या उनके प्रतिनिधि एक साथ बैठेंगे और एक सूची के साथ आएंगे सहमत निर्देश जो इस न्यायालय द्वारा पारित किए जा सकते हैं 6 अप्रैल, 2017"।

10. दुर्भाग्य से, शायद कुछ गलतफहमी या प्रभावी संचार के कारण, सहमत निर्देशों को 8 जुलाई, 2017 को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। उस तारीख को विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने कहाः एक सहमत कार्य योजना पर। हमारी टिप्पणी के साथ सहमत कार्य योजना कुछ मुद्दों पर नीचे दी गई तालिका में बताया गया हैः

सहमत कार्रवाई योजना

दिशा-निर्देश प्रस्तावि लिए महिलाएँ	मंत्रालय राष्ट्रीय	द्वारा मंत्रालय की कार्य योजना आयोग के महिलाएँ और बच्चा का विकास	हमारी टिप्पणी

1.	इंटरैक्टिव डेटा के लिए पहुँच प्रदान करें आधार जो होगा निवेश करने के लिए घर जानकारी के रूप में जल्द ही एक विधवा के रूप में वे प्रवेश करते हैं डेटाबेस होना चाहिए एक प्रोफ़ाइल है विधवा होना समझने में सक्षम उसकी ज़रूरतें [और जल्द से जल्द अपडेट करें] जैसे ही एक विधवा प्रवेश करती है सिस्टम में पोर्टल हो सकता है द्वारा निर्मित सरकार के साथ पहुँच दी गई पंजीकृत घर उन्हें प्रदान करने के लिए इनपुट। सरकार की भारत ने शुरू किया है इस तरह के कार्यक्रम उद्देश्यों के लिए अपनाना	मंत्रालय के महिलाएँ और बच्चा। विकास के अधीन होगा विकास करें।उपयुक्त आधार सक्षम हुआसॉफ्टवेयर के लिए आँकड़ा एकत्र करना प्रणाली संबंधित कैदियों के स्वाधार ग्रेह होना चाहिए। अगले छह के भीतर महीनों और, यदि आवश्यक, एक बाहरी एजेंसी नियुक्त किया जाएगा इसके लिए। पहुँच, तक हद तक की आवश्यकता होगी को प्रदान किया गया अलग-अलग हितधारक और एजेंसी को सौंपा गया है का विकास सॉफ्टवेयर करेगा निर्माण करने के लिए कहें पर्याप्त रूप से सुरक्षा के उपाय उसकी गोपनीय रक्षा करें।	आधार सक्रिय सॉफ्टवेयर अवश्य होगा। लंबित मुकदमेबाजी इस न्यायालय में।
2.	विधवाओं के साथ परिवारों को होना चाहिए पहचान की गई	परिवार की सलाह काम कर रहे केंद्रकेंद्रीय सामाजिक के	अनुवर्ती पोस्टसलाह दी जानी चाहिए स्पष्ट

और उनके परिवार होना चाहिए। के लिए सलाह दी गई ख्याल रखना उन्हें और मामलों में जहाँ आवश्यकता हो। कानूनी कार्रवाई, जैसे वारंट, मई।

तहत कल्याण बोर्ड(सी. एस. डब्ल्यू. बी) और राज्य समाज कल्याण बोर्ड (एस. एस. डब्ल्यू. बी.) देश भर में सौंपा जाएगा की जिम्मेदारी विधवाओं की पहचान करना लिया जाता है जिनके परिवार हैं। की प्रगति किया गया काम करेंगे। द्वारा संकलित किया जाए सीएसडब्ल्यूबी हर महीने और एक रिपोर्ट करने वाला मंत्रालय को हर तिमाही में। सी. एस. डब्ल्यू. बी. इसमें के साथ परामर्श अन्य हितधारक हों विकास करने के लिए कहा छह की अवधि के भीतर महीनों और,इसके बाद, समीक्षा और इसे कब और कैसे अपडेट करें आवश्यकता है।

किया गया है और विशेष रूप से मामलों में परिवार कहाँ है ख्याल नहीं रखते हैं विधवा इसके बाद भी सलाह दी जा रही है।

3.	एनएएलएसए को करना चाहिए एक बनाएँ तंत्र को घरों को सक्षम करें कानूनी सहायता प्राप्त करें।	एनएएलएसए/डीएएलएसए करेगा देने की सलाह दी कानूनी सहायता स्वाधार के कैदी 15 दिनों के भीतर ग्रेह की स्वीकृति द्वारा कार्य योजना माननीय सर्वोच्च अदालत।	
4.	सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों को करना चाहिए निधि का उद्देश्य टी है ए के लिए सीएसआर निधि विधवाएँ प्रबंधन कोष जो होगा विकास के लिए उपयोग किया जाता है व्यावसायिक प्रशिक्षण विधवाओं के लिए।	मंत्रालय ने महिलाएँ और बच्चे विकास हुआ है। के लिए प्रोत्साहित करें पहले से ही लिया गया इससे फर्क पड़ता है लोक विभाग उद्यम और निगम मंत्रालय मामले। बात यह है आगे की कार्रवाई की जाएगी उनके साथ।	संबंधित मंत्रालय को सलाह दी जानी चाहिए सहायता निश्चित रूप से योगदान दें उनका प्रतिशत और लाभ बेसहारा विधवाएँ।
5.	सरकार चिकित्सा का पता लगाएं सभी के लिए बीमा विधवाएँ और कम से कम विधवाएँ जो हैं में रखा गया स्वाधार होम्स सो वह अच्छी चिकित्सा सुविधाएं हो सकती	सभी राज्यों और संघों में क्षेत्र, दवाएँमुफ्त में दिया जाता है रोगियों के लिए लागत आम लोगों के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	इसका लाभ मुफ्त की आपूर्ति मुफ्त की आपूर्ति सक्रिय होना चाहिए दवाएँ होनी चाहिए के लिए उपलब्ध कराया गया

	हैं द्वारा पहुँचा गया विधवाएँ सभी को सलाह देने का अनुरोध कियास्वाधार में रहना प्रशासन कोउन सभी के लिए सुनिश्चितघर।	राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय परिवार कल्याण। यह हो सकता है,इसलिए, नहीं हो चिकित्सा बीमा को ऐसे उपाय के रूप में लागू करना आवश्यक है विधवाओं की आय का एक हिस्सा छीन लो और उन्हें गरीब बना दो आगे। स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय कल्याण हो गया सभी राज्य सरकारों को सलाह देने की आवश्यकता है और यूनियन टेनिटोल)' प्रशासन को निःशुल्क दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करें उन सभी को सुनिश्चित किया गया स्वाधार में घूमना घर.	असहाय महिलाओं के रूप में ठीक है। की उपलब्धता मुफ्त चिकित्सक विचार करने की आवश्यकता है। परिचय देना आवश्यक है
6.	गृह मंत्रालय होना चाहिए	कौशल विकास और	

	वर्तमान से जुड़ा हुआसरकारकार्यक्रम घरों को होना चाहिए के लिए प्रोत्साहित किया और खोलें के लिए रास्ते विधवाओं के कौशल; में विधवाएँ देखभाल और आतिथ्य क्षेत्र चिपके रहने से ज़्यादा सिलाई आदि। जो नहीं उपलब्ध कराएँ व्यवहार्य के लिए रोजगार इस दिशा में प्रगति विधवाओं और इसलिए मजबूर करता है उनमें रहने के लिए इन घरों में। विकास और उद्यमिता	उद्यमिता हाँ। अनुरोध किया गया हैएक योजना बनाने के लिए के लिए कार्रवाई का विकास को नियोजित करना और अनाथ, बेसहारा और उपेक्षित महिलाओं द्वारा क्षेत्रीय कौशल विकास परिषदें। वे. आर्थिक रूप से भी रहे हैं। अनुरोध किया गया कि निगरानी करें नियमित रूप से ध्यान दें अंतराल।महिला एवं बाल मंत्रालय विकास होगा संलग्न रहना जारी रखें मंत्रालय के साथ कौशल विकास और उद्यमिता के लिए सुनिश्चित करना का विकास सूट एब ले मॉड्यूल कौशल विकास के लिए.
7.	स्वाधार के कर्मचारी घर होना चाहिएसमय-समय पर प्रशिक्षित और होना भी	राष्ट्रीय संस्थान सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास (एन. आई. पी. सी. सी. डी.)

चाहिए उचित रूप से, क्षतिपूर्ति की गईआर्थिक रूप से।	पर्याप्त और महिला और बाल विकास मंत्रालय बाल विकास है पहले से ही अनिवार्य विभिन्न को प्रशिक्षण प्रदान करें हितधारकों सहित सहित विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना स्वाधार गृह के कर्मचारी। प्रशिक्षण पर निर्भर करता है मूल्यांकन की जरूरत है, सीएस डब्ल्यूबी भी ऐसा हो सकता है यह सौंपा गया ज़िम्मेदारी। प्रावधान के लिए बनाया गया है प्रेरण प्रशिक्षण प्रदान करना और बाद में आवधिक नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण

		के स्टाफ को समय की स्वाधार गृह.	
८.	तत्काल कार्रवाई सुधार करने के लिए की आधारभूत संरचना घर और इसे बनाए रखने के लिए धन।	इसके अलावा स्वाधार गृह योजना के माध्यम से लागू किया जा रहा है देश से बाहर, महिला और बाल विकास मंत्रालय डेवलपमेंट है निर्माण शुरू किया एक नये 1000 बिस्तर का स्वाधार गृह,वृन्दावन, जिला. मथुरा।इसे डिज़ाइन किया गया है बुढ़ापे में मिलनसार और इच्छाशक्ति के साथ शयनगृह हैं संलग्न शौचालय और उपयोगिता बालकनियाँ स्वालहर गृह में भी सुविधा होगी फिजियोथेरेपी के लिए, खुला रंगमंच, व्यावसायिक	राज्य सरकार होना चाहिए टी को अपनाना नियोजित टी मंत्रालय।

प्रशिक्षण,

सोला- जी पीवाई, सौर

जल तापन प्रणाली,

बहुउद्देशीय हॉल, आदि

की अपेक्षित तिथि

इस स्वालहर को पूरा करना

ग्रेह जनवरी, 2018 है।

पेंशन			
1.	यह मिल गया वह वर्तमान का आवंटन पेंशन या तो थीअपर्याप्त या अस्तित्वहीन. प्राथमिक चिंताएँ जिससे उत्पन्न हुआ अनुसंधान वह पेंशन राशियाँ नहीं थीं लागत से जुड़ा हुआ जीने की। वहाँ कोई तर्क नहीं था के लिए गणना राशिया में छत की संख्या लाभार्थियों कि पेंशन सकता है में दिया जाए कोई भी	तुलना बीच पेंशन की राशि द्वारा प्रदान किया गया सरकार और न्यूनतम देय मजदूरी विभिन्न के अंतर्गत सरकार जनाएं फ़्यूर नहीं हैं. जबकि, पेंशन है कल्याण के रूप में भुगतान किया गया बिना मापें कोई भी सेवा हो द्वारा प्रस्तुत किया गया	पेंशन, किराये के रूप में उपाय हो सकता है लागत से जुड़ा हुआ है। जीवन सूचकांक का और नहीं होना चाहिए मनमाने ढंग से तय किया गया।

	राज्य. पेंशन होनी चाहिए लागत के आधार पर लिविंग इंडेक्स का और इसलिए यह चालू होना चाहिए के बराबर वेतन एक अकुशल का कार्यकर्ता के साथ संगत के रूप में क्रीज में न्यूनतम मजदूरी बढ़ती है।	लाभार्थी, पारिश्रमिक है सेल्विस के लिए द्वारा प्रस्तुत किया गया श्रमजीवी। यदि दो होने थे बराबर, यह एक होगा प्रमुख हतोत्साहन सक्षम शरीर के लिए व्यक्ति को कोई भी कार्य करना है काम	

आश्रयों की संरचना और कार्यप्रणाली			
1.	एक बहु-वैकल्पिक मॉडल नियोजित किया जाए संस्थागत के लिए आश्रय। आश्रय को पूरा करने के लिए बनाया जा सकता है की आवश्यकता उपयोगकर्ता के आधार पर एक रात के लिए संबंधित उपयोगकर्ता शुल्क आश्रय, एक दिन का आश्रय या एक पूर्णकालिक आश्रय.	उपयोगकर्ता-शुल्क का भुगतान वह व्यक्ति कर सकता है जो कमा रहा है। स्वाधार योजना उन महिलाओं की मदद करती है जो गरीबी की खाई में हैं और किसी का भुगतान उनके द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क परे होगा उनके साधन हालाँकि, महिला छात्रावास	

		होंगे होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए द्वारा स्थापित राज्य और संघ क्षेत्र.]	
2.	एकीकरण को निर्देशित करें स्वाधार होम, स्वाधार होम और अल्पावास गृह की अल्पावास गृह और अन्य समान स्थान विधवा पुनर्वास के लिए निर्देशित नीतियों के सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा के लिए सुविधा गृह।	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की दो योजनाएं स्वाधार गृह और अल्पावास गृह हैं। पहले से ही नए में विलय कर दिया गया है योजना अर्थात् स्वाधार गृह प्रभावी 01.01.2016. यह योजना है राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित/यूटी प्रशासन से वित्त पोषण के साथ सरकार. भारत.	सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए के साथ आयोजित के बारे में कार्यान्वयन योजनाओं का.
3.	छत बढ़ाएँ तीन वर्ष की सीमा जो महिलाएं अंदर रह रही हैं स्वाधार होम्स में प्रभावी ढंग से करने का आदेश के जीवन को स्थिर करें	के लिए प्रस्ताव के लिए सीमा बढ़ाना स्वधार में रहना महिलाओं के लिए गृह 55 वर्ष से ऊपर के लाभार्थी वर्ष की आयु कम है का विचार	

	कैदी.	सरकार और ए इस संबंध में निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा.	
4.	संरचनात्मक एकीकरण वृद्धाश्रमों में आश्रय; इस कोने तक, का चिकित्सीय मूल्यांकन बीच-बीच में महिलाएं 60 से 65 वर्ष की आयु आश्रयों में उम्र का पर आयोजित किया जाए जिसके आधार पर महिलाएं जारी रख सकती हैं में निवास करना आश्रय।	का मंत्रालय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण है करने का अनुरोध किया गया है विधवाओं को समायोजित करें स्वाधार गृह से वृद्धाश्रम चालू 60 वर्ष की आयु प्राप्त करना साल। आव श्यक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी एजेंसियों से बंधा होना चाहिए से संबंधित है स्थानीय	

		सी.एच.सी./पी.एच.सी.	
		स्वास्थ्य और पोषण	
1.	को एकीकृत करने के लिए के प्रयास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी स्वाधार योजना. घरों का लिंकेज कि घर की बूढ़ी महिलाओं के साथ चिकित्सा औषधालय इसकी सिफारिश की जाती है।	जैसा कि ऊपर बताया गया है, निःशुल्क दवाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. द्वारा के अंतर्गत सभी मरीज़ मंत्रालय के एन.एच.एम स्वास्थ्य एवं परिवार का कल्याण और मंत्रालय रहा है सभी को सलाह देने का अनुरोध किया राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को तक पहुंच सुनिश्चित करें	

		मुफ़्त दवाएँ है उन सभी को सुनिश्चित किया गया स्वधार में रहना घर.	
2.	का उपयोग विधवा पेंशन के लिए योजना चिकित्सा की खरीद सुविधाएँ	विधवा पेंशन को भुगतान किया जाता है व्यक्तियों. में की रोशनी की उपलब्धता दवाइयां निःशुल्क लागत, जैसा बताया गया है ऊपर, यह नहीं हो सकता है के लिए आवश्यक हो पेंशन डायवर्ट करो के लिए राशि दवाओं की खरीद.	

कानूनी फीस और व्यय का कवरेज			
1.	नालसाण्ड DALSATO आवंटित उपयुक्त कवर करने के लिए मंजूरी कानूनी छूट विधवाओं का कानूनी में शामिल मायने रखता है, और आकस्मिक खर्चे आए आवागमन के लिए और इसी तरह और इसी तरह आगे.	कैदी स्वाधार गृह पहुंच होगी निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु द्वारा उपलब्ध कराया गया नालसंडालसा और आवश्यक सलाह होगी इसमें जारी किया गया संबद्ध।	
व्यावसायिक प्रशिक्षण			
1.	मंडतोइ और का आयोजन किया व्यावसायिक प्रशिक्षण में महिलाओं की आश्रयों को छोटा सा भूत कला कौशल सेट एक के लिए आवश्यक है सामान्य जीवन और को	जैसा कि ऊपर कहा, के मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमशीलता रहा है करने का अनुरोध किया एक तैयार करें योजना के लिए कार्रवाई की का	

	ई.उन्हें सक्षम करें सम्मानजनक कमाओ आजीविका।	विकास के कौशल विधवाएं और अनाथ, निराश्रित और हाशिये पर डाल दिया गया महिलाओं के माध्यम से क्षेत्रीय कौशल विकास परिषदें। वे क्या तुम भी थे करने का अनुरोध किया की निगरानी इसमें प्रगति नियमित रूप से सम्मान अंतराल. मंत्रालय महिला एवं बाल विकास होगा करने के लिए जारी के साथ संलग्न हों कौशल मंत्रालय विकास और उद्यमशीलता सुनिश्चित करने के लिए का विकास उपयुक्त मॉड्यूल.	
स्वीकृतियाँ प्रदान करना			
1.	संबंधित एजेंसियों को घरों के समुचित मकाज के लिए आवश्यक बजट प्रदान करने	स्वाधार गृह योजना की वित्तीय शर्तों को दिनांक 01.10.2017 से संशोधित	हर छह माह में नॉन की समीक्षा की जानी चाहिए।

	के लिए मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधों में वृद्धि आवधिक और सामयिक को अनुदान जारी करना सुविधा दें निरंतरता और का भरण-पोषण घर.	किया गया है। 01.01.2016 और आगे की जांच पर, विभाग व्यय ने राय दी है कि ये फिलहाल पर्याप्त हैं।	
घरों की समय-समय पर समीक्षा			
1	वह राष्ट्रीय के लिए कमीशन महिलाओं को निर्देशित किया जाए समीक्षा करने के लिए मौजूदा का अध्ययन करने के लिए विधवाओं की स्थिति हमारे घर निकट में देश भविष्य।	राष्ट्रीय के लिए कमीशन महिलाएं ले सकती हैं उचित कार्यवाही लेने के लिए प्रस्तावित समीक्षा मौजूदा का अध्ययन करें विधवाओं की स्थिति घर.	
2.	इस प्रयोजन के लिए, ग्रामीण मंत्रालय द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाएगा, सामाजिक न्याय और	राष्ट्रीय महिला आयोग ले जा सकता है उपलब्ध मौजूदा निधियों से अपना अध्ययन करें उनके साथ। यदि उनके	मंत्रालय को चाहिए धन को लेकर कंजूसी न करें, खासकर अच्छे उद्देश्य के लिए।

	अधिकारिता मंत्रालय और महिला मंत्रालय एनसीडब्ल्यू द्वारा बच्चों का सर्वेक्षण किया जाएगा।	द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती है तो धनराशि की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।	
3.	एक आवधिक आदेश दें घरों की समीक्षा हर पांच साल में आई.आई.टी राज्य एवं जिला स्तर पर समय-समय पर आचरण करें का निरीक्षण घरों को सुनिश्चित करने के लिए का उचित कार्यान्वयन योजनाएं और घरों की कार्यप्रणाली और डीपीओ द्वारा अभिलेखों की निगरानी की गई (जिला परियोजना अधिकारी)। सालाना 3 के लिए। साल और फिर हर 3 साल में।	स्वाधार गृह योजना में एक अंतर्निहित निगरानी तंत्र है। घरों की निगरानी स्तरीय माध्यम से की जाती है संरचना अर्थात. जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर। स्वाधार गृह को शुरुआत में पांच साल की अवधि के लिए मंजूरी दी जाएगी साल। योजना लागू होने के बाद 5 वर्ष, परियोजना मंजूरी समिति इस पर निर्णय लेगी आगे तक जारी रखना या अन्यथा उसके प्रदर्शन और आवश्यकता पर निर्भर करता है	

जागरूकता का सृजन			
1.	जागरूकता फैलाने के लिए ग्रामीण और जिला स्तर पर संलग्न होना शेरेस का अस्तित्व स्वधार हेम्स एन के समान है: द्वारा प्रयोज्य अधिकारों का ज्ञान प्रदान करना महिलाओं को समान स्थिति में रखा गया।	स्वाधार गृह योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है राज्य सरकारें. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जागरूकता पैदा करेंगे। स्वाधार गृह के बारे में जानकारी प्रसारित करना स्वाधार गृह विभिन्न तरीकों से। योजना के एक भाग के रूप में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।	

11. यह भी हमारी राय है कि सभी संबंधित लोगों द्वारा किए गए प्रयास जिन रिपोर्टों को हमने ऊपर बताया है, वे व्यर्थ नहीं जाने चाहिए- इसका लाभप्रद रूप से उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक तरह से व्यावहारिक और व्यावहारिक सोने की खान है। व्यवहार्य सुझाव। तदनुसार, हम इस न्यायालय में दायर सभी रिपोर्टों का अध्ययन करने और दो महीने की अवधि के भीतर और किसी भी मामले में 30 नवंबर, 2017 को या उससे पहले हमें एक सामान्य कार्य योजना (रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के आधार पर) प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन करते हैं। द. समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे (महिला और बाल विकास मंत्रालय के निर्देश पर विद्वान

सॉलिसिटर जनरल द्वारा सुझाए गए पहले दो और राष्ट्रीय स्तर के विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए तीसरे सुझाव)।

महिला आयोग):

1. एनजीओ जागोरी की सुश्री सुनीता धर,

2. गिल्ड फॉर सर्विस की सुश्री मीरा खन्ना

3. सुश्री आभा सिंघल जोशी, वकील और कार्यकर्ता

4. हेल्पएज इंडिया का एक नामांकित व्यक्ति, एक गैर सरकारी संगठन जिसने प्रदान किया है इस मामले में मूल्यवान सहायता।

5. सुलभ इंटरनेशनल के एक नामांकित व्यक्ति, एक गैर सरकारी संगठन जिसने प्रदान किया है इस मामले में

6. सुश्री अपराजित सिंह, इस न्यायालय में वकालत करने वाली एक वकील, कानूनी मुद्दों पर कोई भी सहायता।

12. याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जिन मुद्दों का उल्लेख किया गया था, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में उनका उल्लेख नहीं किया गया है, उनमें से एक है विधवाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता। पुनर्विवाह। यह आशा का विषय है जो हमारे समाज को विधवाओं के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण को छोड़ने में सक्षम बना सकता है। हम समिति से अनुरोध करते हैं कि विचार-विमर्श के दौरान इस पर विचार करें।

13. हम राष्ट्रीय महिला आयोग से सार्वजनिक रूप से अनुरोध करते हैं समिति को कुछ कार्य स्थान प्रदान करने में सहायता करने के लिए। हम समिति को मानदेय के साथ पर्याप्त पारिश्रमिक देने का प्रस्ताव करते हैं। इसका फैसला तब किया जाएगा

जब मामले की अगली सुनवाई होगी। रजिस्ट्री यह सुनिश्चित करेगी कि सभी रिपोर्ट सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएं। समिति। एल (1982) 3 एस. सी. सी. 235

14. कार्य योजना और ये निर्देश क्यों आवश्यक हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि हम जनहित याचिका की शक्ति को भूल रहे हैं और इसलिए समय-समय पर, प्रदान करने में इसकी प्रभावकारिता के बारे में खुद को याद दिलाने की आवश्यकता है सामाजिक न्याय। कई साल पहले, इस न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम में उल्लेख किया था। भारत संघ 'वह

> "जनहित याचिका अदालत के समक्ष लाई जाती है न कि एक व्यक्ति के दूसरे के खिलाफ अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से यह सामान्य मुकदमेबाजी के मामले में होता है, लेकिन इसका उद्देश्य सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना और सही साबित करना है जो बड़ी संख्या में गरीब, अज्ञानी या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित लोगों के संवैधानिक या कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की मांग करता है। स्थिति पर किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए और बिना बदले नहीं जाना चाहिए। यह कानून के शासन के लिए विनाशकारी होगा जो सरकार के किसी भी लोकतांत्रिक रूप में सार्वजनिक हित के आवश्यक तत्वों में से एक है। थोड़ी देर बाद फैसले में कहा गयाः

> "मानवता के वंचित और कमजोर वर्गों से संबंधित लाखों लोग अपनी स्थिति में सुधार के लिए अदालतों की ओर देख रहे हैं। जीवन की स्थिति और उनके लिए बुनियादी मानवाधिकारों को सार्थक बनाना। वे न्याय के लिए रोते रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ अब तक जंगल में रही है। वे चुपचाप अन्याय झेल रहे हैं। एक चट्टान का धैर्य, बिना किसी ताकत के, यहाँ तक कि किसी को भी छोड़ने के लिए आँसू"।

15. जनहित याचिका का लाभ सिर्फ इतना ही नहीं है समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी सशक्त बनाना उन सामाजिक विकलांगताओं से पीड़ित लोगों को सशक्त बनाना जो आवश्यक नहीं हैं उनके निर्माण का. वृन्दावन की विधवाएँ (और वास्तव में अन्य आश्रमों में भी) यह स्पष्ट रूप से हमारे सामाजिक रूप से वंचित वर्ग समाज की इस श्रेणी में आता है।

16. सशक्तीकरण को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, इस न्यायालय ने राज्य में उल्लेख किया उत्तरांचल बनाम। बलवंत सिंह चौफाल ने कहा कि जनता का पहला चरण ब्याज मुकदमेबाजी मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत "समाज के हाशिए पर पड़े समूहों और वर्गों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है जो चरम सीमाओं के कारण हैं। गरीबी, निरक्षरता और अज्ञानता इस न्यायालय या उच्च न्यायालयों से संपर्क नहीं कर सकते। हम जोड़ सकते हैं-सामाजिक रूप से वंचित समूह। ये हैं। जिन लोगों के पास न्याय तक कोई वास्तविक पहुंच नहीं है और उस अर्थ में हैं बेजुबान, और ये वे लोग हैं जिन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है और जिनके कारण को उन लोगों द्वारा समर्थित करने की आवश्यकता है जो सामाजिक समर्थन करते हैं वंचितों के लिए न्याय।

17. यह मान्यता दिल्ली जल बोर्ड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय का आधार बनी। गरिमा और अधिकारों के लिए राष्ट्रीय अभियान मलजल निकासी और उससे जुड़े कर्मचारी जिनमें वंचितों को सहायता प्रदान की जाती है समाज के वर्गों को इसके "संवैधानिक कर्तव्य" के रूप में मान्यता दी गई थी। अदालत। इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों का उल्लेख करते हुए यह कहा गयाः

> "ये निर्णय द्वारा दायर रिट याचिका की स्थिरता पर अपीलार्थी की आपत्ति का पूरा जवाब हैं। प्रत्यर्थी ।. उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करके और व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी करके क्या किया है सीवेज

संचालन से संबंधित कार्य करने के लिए नियोजित होना वंचित और गरीब वर्गों के साथ न्याय करने के अपने दायित्व का हिस्सा है। समाज को। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि उच्च न्यायालय अपने संवैधानिक कर्तव्य में विफल होंगे यदि वे वास्तविक सामाजिक समूहों, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करने से इनकार करते हैं। उन लोगों का कारण जो प्रत्येक मनुष्य के लिए उपलब्ध बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं, संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के बारे में क्या कहना है। अपने राजनीतिक और कार्यकारी घटकों की तरह राज्य के न्यायिक घटक का यह कर्तव्य है कि वह न्यायपालिका की रक्षा करे। प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और यह सुनिश्चित करना कि सभी सम्मान के साथ जीने में सक्षम है।" 2(2010) 3 एस.सी.सी 402।

18. इसमें बहुत कम या कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कुछ हिस्सों में विधवाएँ होती हैं। देश के लोग सामाजिक रूप से वंचित हैं और कुछ हद तक बहिष्कृत हैं। शायद यही कारण है कि उनमें से कई वृंदावन और अन्य आश्रमों में आने का विकल्प चुनते हैं, जहां दुर्भाग्य से, उनके साथ उस सम्मान के साथ व्यवहार नहीं किया जाता है जिसके वे हकदार हैं। यह उस लेख से स्पष्ट है जो इस जनहित याचिका का कारण बना और उन रिपोर्टों के संकलन से जो इस मुकदमे ने उत्पन्न की हैं। इन असहाय विधवाओं को आवाज देने के लिए इस न्यायालय के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्य के हिस्से के रूप में और सामाजिक न्याय के कारणों से उचित निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया।

19. हमें याचिकाकर्ताओं, मंत्रालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए महिला और बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रयासों के लिए और

विशेष रूप से सुश्री रेणुका कुमार के लिए, जिन्होंने अपनी रिपोर्टों के माध्यम से इस न्यायालय की बहुत सहायता की है।

20. प्रस्तुत सहमत कार्य योजना पर अनुवर्ती कार्रवाई करने की दृष्टि से विद्वान महान्यायवादी द्वारा इन मामलों को 9 अक्टूबर, 2017 को सूचीबद्ध करें।

दिव्या पांडे निर्देश जारी किए गए।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।